राज्य सरकार जिला आधारित विकास मॉडल पर कार्य कर रही है- भजनलाल

मुख्यमंत्री व प्रो.के.वी. राजू ने जिला घरेलू उत्पाद अनुमान पर बैठक को संबोधित किया

जयपुर, 22 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में राजस्थान अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार जिला आधारित विकास मॉडल को प्राथमिकता देते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान, स्थानीय संसाधनों और आर्थिक संभावनाओं को केन्द्र में रखकर विकास की नई अवधारणा विकसित की जा रही है, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में स्टार्टअप इको सिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है तथा वर्तमान में 6 हजार से अधिक सक्रिय स्टार्टअप रोज़गार प्रदान कर रहे हैं।**
- **नीति आयोग के सदस्य प्रो. राजू ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान अचीवर्स श्रेणी का प्रदेश है।**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर के. वी. राजू ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर "जिला घरेलू उत्पाद अनुमान" विषय पर आयोजित बैठक को संबोधित किया।

सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर के. वी. राजू की उपस्थिति में "जिला घरेलू उत्पाद अनुमान" विषय पर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग, निवेश और सुशासन आधारित नीतियों के कारण बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हो रहा है। प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी तेजी से विकसित हो रहा है तथा वर्तमान में 6 हजार से अधिक सक्रिय स्टार्टअप्स युवाओं को रोजगार और नवाचार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं।

प्रो. के.वी. राजू ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान अचीवर्स श्रेणी का प्रदेश है और यहां पेयजल तथा ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं में अच्छा कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन, कृषि, खनन और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र, उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण पर गंभीरता से कार्य कर रही है। इससे चूरू के हस्तशिल्प उद्योग, भरतपुर के सरसों आधारित छोटे उद्यम तथा बांसवाड़ा एवं उदयपुर के आदिवासी क्षेत्रों में निर्मित पारंपरिक जनजातीय उत्पादों जैसे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत उद्यमों को संगठित अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनने का अवसर मिल रहा है।

बैठक में राजस्थान के प्राथमिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने संबंधी एवं राज्य के आर्थिक परिदृश्य तथा मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया गया। इस दौरान मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास सहित, संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे एवं सभी संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर वी.सी के माध्यम से जुड़े।

मई में केन्द्र व राज्यों में 159 दवाओं के सैम्पल फेल हुए

नई दिल्ली, 22 जून। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरीज ने मई के लिए अपनी मासिक ड्रग अलर्ट रिपोर्ट में अलग-अलग कंपनियों द्वारा बनाई गई 46 दवाओं के सैंपल को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया। अधिकारियों ने बताया कि इसके अलावा राज्य स्तरीय दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं ने 113 दवाओं के सैंपल को भी एनएसक्यू पाया है।

बता दें कि यह जानकारी नियमित निगरानी प्रक्रिया के तहत एनएसक्यू और नकली दवाओं की सूची हर महीने सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) के पोर्टल पर जारी की जाती है।

बैंक खातों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि पार्टी के तीन बैंक खातों पर रोक लगाने की कार्रवाई बगैर प्रारंभिक जांच के की गई। पार्टी का कहना है कि पुलिस ने शिकायत की सत्यता की पड़ताल किए बिना ही खातों के खिलाफ कठोर कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे संगठन के नियमित कामकाज पर गंभीर असर पड़ा है। यह कार्रवाई तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक विश्वनाथ दास की शिकायत के बाद की गई थी। दास ने पार्टी के बैंक खातों और धन के उपयोग को लेकर कथित बड़े वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है।

ब्रिटेन के प्र.मंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफा दिया

कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी का नेतृत्व भी त्याग दिया तथा कहा कि नए प्र.मंत्री के आने तक वे पद पर बने रहेंगे

लंदन, 22 जून। ब्रिटेन की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए कहा है कि अब पार्टी को नए नेतृत्व की ओर बढ़ ना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे, ताकि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी की जा सके।

- **लेबर पार्टी में जोर शोर से नए नेता की तलाश की जा रही है। राजनैतिक हलकों में एंडी बर्नहम को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।**

डाउनिंग स्ट्रीट से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि नए नेता के चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और पार्टी की आंतरिक चुनाव प्रक्रिया के बाद नया नेतृत्व तय किया जाएगा। अपने संबोधन में स्टार्मर ने कहा कि वे अपने उत्तराधिकारी को पूरा समर्थन देंगे और उन्हें विश्वास है कि नया नेतृत्व देश को आगे बढ़ ाने का काम करेगा। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया और कहा कि उन्होंने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली थी, जब पार्टी कई चुनौतियों का सामना कर रही थी।

लेबर पार्टी के भीतर अब नए नेता की तलाश तेज हो गई है। राजनीतिक हलकों में एंडी बर्नहम को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। उन्होंने नेतृत्व चुनाव में उतरने के संकेत भी दिए हैं और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन उन्हें मिल रहा है।

स्टार्मर ने वर्ष 2020 में लेबर पार्टी का नेतृत्व संभाला था और 2024 के आम चुनाव में पार्टी की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि, हाल के महीनों में पार्टी के भीतर उनकी नीतियों और नेतृत्व शैली को लेकर असंतोष बढ़ ता दिखाई दिया।

बागी सांसदों के क्षेत्रों का उद्धव ठाकरे दौरा करेंगे

शिवसेना यूबीटी बागी नेताओं के खिलाफ सीधा आक्रामक मोर्चा खोलेगा

मुंबई, 22 जून। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर हुआ है। शिवसेना-यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के बागी सांसदों के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। उद्धव ठाकरे आगामी 27 से 29 जून तक राज्य के उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों का तूफानी दौरा करेंगे, जहां के सांसदों ने हाल ही में पाला बदलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी के भीतर हुए इस बड़े विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे का यह पहला और सबसे आक्रामक कदम माना जा रहा है।

- **पार्टी 27 से 29 तक, तीन दिन अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार रही है। हर सीट के लिये विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपी गई है।**

राज्यसभा सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह तीन दिवसीय दौरा राज्य के कई सबसे महत्वपूर्ण जिलों को कवर करेगा। पार्टी की तरफ से इस महा दौरे को बेहद आक्रामक बनाने के लिए शीर्ष नेताओं को मैदान में उतारा गया है और हर लोकसभा क्षेत्र के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

पार्टी को लगे इस करारे झटके के बाद, उद्धव ठाकरे ने बेहद भावुक और रणनीतिक दांव खेला है। ठाकरे ने पहले ही एलान कर दिया है कि वे सीधे इन निर्वाचन क्षेत्रों की जनता के बीच जाएंगे। वे 2024 के आम चुनावों के दौरान इन दलबदलू सांसदों को वोट देने वाले मतदाताओं से सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे कि उन्होंने गलत उम्मीदवारों को टिकट दिया।

तय कार्यक्रम के मुताबिक, उद्धव ठाकरे 27 जून को यवतमाल से अपने इस शक्ति प्रदर्शन वाले दौरे की शुरुआत करेंगे। दौरे के अंतिम दिन, 29 जून को उद्धव ठाकरे पवित्र नगरी शिरडी का दौरा करेंगे। शिरडी में इस बेहद महत्वपूर्ण चरण की देखरेख का जिम्मा खुद संजय राउत और एमएलसी सुनील शिंदे को सौंपा गया है। इससे पहले, संयुक्त शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से एक बेहद भावुक अपील की थी। उन्होंने पिछले शुक्रवार को कहा था कि अगर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बागी सांसदों की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों को सही मानते हैं, तो वे तुरंत शिवसेना-यूबीटी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद, अब इस जमीनी दौरे को शिंदे गुट के खिलाफ आर-पार की लड़ाई माना जा रहा है।

टीएमसी के बागियों ने ममता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आधिकारिक प्रचार सामग्री से औपचारिक रूप से हटा दिया है।

बागी सदस्यों के इस अधिवेशन में वरिष्ठ नेता अरूप रॉय को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने ममता बनर्जी का स्थान लिया है।

बागी नेता ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि यह विशेष अधिवेशन पार्टी में उत्पन्न संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए बुलाया गया था। उनका दावा था कि पार्टी में विभिन्न पदों के लिए वैध चुनाव नहीं कराए गए थे। उनके अनुसार, पार्टी के आंतरिक चुनाव नहीं होने के कारण पूर्व राष्ट्रीय समिति और उसकी कार्यकारी संस्थाएं अमान्य हो गईं।

ऋतब्रत बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के चुनाव के लिए पहली बार औपचारिक अधिवेशन बुलाया गया है। सभी बागी सदस्य अल्पमत में आ चुके ममता बनर्जी गुट को घेरने के लिए एकजुट हुए हैं।

गुट ने नई राष्ट्रीय कार्यसमिति की भी घोषणा की। ऋतब्रत बनर्जी और अरूप रॉय के अलावा, कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी सहयोगियों में रहे फिरहाद हाकिम को भी राष्ट्रीय कार्यसमिति में शामिल किया गया है। इसके साथ ही, विद्रोही गुट के कई अन्य नेताओं को भी कार्यसमिति में जगह दी गई है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्टी पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के पहले कदम के रूप में बागी गुट ने निर्वाचन आयोग से पार्टी के बैंक खातों की भी जांच कराने का अनुरोध किया है। पार्टी के पुराने खातों में अभी भी पर्याप्त धनराशि मौजूद बताई जा रही है।

यदि विद्रोहियों का यह प्रयास सफल हो जाता है, तो यह उस नेता के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक अपमान होगा, जिसने 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी और उसे उल्लेखनीय राजनीतिक सफलता तक पहुंचाया था। ऐसी स्थिति में, ममता बनर्जी अपनी ही बनाई पार्टी पर नियंत्रण खो देंगी और उनकी आंखों के सामने ही पार्टी का नियंत्रण उनके ही संगठन के एक कनिष्ठ नेता के हाथों में चला जाएगा।

बागी गुट ने पार्टी कोष पर भी दावा जताया है और उसे तत्काल प्रभाव से फ्रीज़ करने की मांग की है। इससे पुराने नेतृत्व के सामने संसाधनों की कमी की स्थिति पैदा हो सकती है।

भारत तिवारी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गोली मार दी, स्वयं योगी आदित्यनाथ को अपना आदर्श बताते थे। उन्होंने स्वयंभू धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम आश्रम तक एक यात्रा भी निकाली थी। ज्ञातव्य है कि धीरेन्द्र शास्त्री को आरएसएस-भाजपा के एजेंडे का समर्थक माना जाता है। अपने फेसबुक पेज पर तिवारी ने खुद को क्रांतिकारी और शहीद सरदार भगत सिंह का अनुयायी बताया था। भोजपुर जिले के अपने बिलौती गांव में वे बाढ़, विस्थापन और निचले स्तर की नौकरशाही में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले ऐक्टिविस्ट के रूप में पहचान बना चुके थे। उनकी मौत से न केवल जनता के बीच हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे हैं, बल्कि इससे राज्य की मौजूदा सरकार भी असहज स्थिति में आ गई है। विपक्षी नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं, भाजपा के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे और पूर्व विधायक राजन तिवारी जैसे, भाजपा नेताओं ने भी इस घटना को "नृशंस हत्या" बताया है। जनवरी में केन्द्र सरकार द्वारा यूजीसी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव लाए जाने के बाद, बिहार के कुछ वर्गों ने भाजपा नेतृत्व पर "ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगाया था, अब तिवारी की हत्या के बाद ये आरोप और मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं।

ईरानी तेल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के दौरान ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को बाधित न करने का आश्वासन दिया है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी सकारात्मक संकेत मिलने की बात कही जा रही है।

लखनऊ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिजनों से मिलने व घायलों का हालचाल जानने के बाद मुख्यमंत्री ने देर रात यह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इसमें मुख्यमंत्री ने घटना को लेकर काफी रोष जताते हुए दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाया गया। इसके सदस्य 07 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

'राम मंदिर चंदा प्रकरण की जांच एसआईटी करे'

नई दिल्ली, 22 जून। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दान की कथित चोरी की सीबीआई के नेतृत्व में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को निर्देश देने की मांग की गई है कि वो वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित करें, क्योंकि इससे करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। याचिका दो वकीलों अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि उप्र सरकार की ओर से गठित एसआईटी ने बिना कोई एफआईआर दर्ज किए ही जांच शुरु कर दी है।

- **सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश।**

अड़तालीस घंटे में मानसून मुंबई पहुंचेगा

गोवा, कोंकण, बिहार में भारी वर्षा की संभावना, विदर्भ, पूर्वी मध्यप्रदेश भीषण लू की चपेट में

नई दिल्ली, 22 जून। तपती और झुलसाती गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अगले 48 घंटों में इसके मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र को अपने आगोश में लेने की पूरी उम्मीद है, जिससे लोगों को भीषण उमस से राहत मिलेगी। मानसून अब तक तेलंगाना, छत्तीसगढ़ , ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई हिस्सों में दस्तक दे चुका है।

एक तरफ जहां मानसून राहत लेकर आ रहा है, वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बन गया है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम सहित, कई राज्यों में 28 जून तक भारी से अत्यंत भारी बारिश (20 सेंटीमीटर से अधिक) का अलर्ट जारी किया गया है। मेघालय में बाढ़ जैसे हालात की आशंका है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

- **मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम, मेघालय, अरुणाचल व सिक्किम में 28 जून तक भारी वर्षा की चेतावनी।**

उर्वरक से भरे चार भारतीय जहाजों ने होर्मुज़ पार किया

नई दिल्ली, 22 जून। भारत सरकार की तरफ से सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, फारस की खाड़ी से यूरिया, डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और सल्फर की खेप लेकर आ रहे चार मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह सुरक्षित रूप से होर्मुज़ जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं। ये जहाज अब भारत के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार के अनुसार, ये जहाज कृष्णापटनम, काकीनाडा, पारादीप और मुंद्रा बंदरगाहों पर पहुंचेंगे। यहां पहुंचते ही खाद की खेप को तेजी से उतारा जाएगा, ताकि किसानों को समय पर खाद आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके और देश के खाद भंडार को और मजबूत बनाया जा सके।

- **किसानों को समय पर खाद की आपूर्ति हो सकेगी।**

प.बंगाल सरकार के पहले बजट में एक लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा

भाजपा सरकार ने 4.38 लाख करोड़ का बजट पेश किया, कर्मचारियों व पेंशन भोगियों का डीए बढ़ाया

कोलकाता, 22 जून। पश्चिम बंगाल की पहली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्त ने बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य में रोजगार सृजन, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, औद्योगिक निवेश और आधारभूत संरचना के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। बजट में एक लाख सरकारी रिक्त पदों पर नियुक्ति, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ी वृद्धि, बेरोजगार युवाओं के लिए नई सहायता योजना तथा कई बड़ी बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की घोषणा की गई है।

- **वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देगा, रोजगार बढ़ायेगा तथा सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा।**

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वर्तमान सरकार को पूर्ववर्ती सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का संचित ऋण विरासत में मिला है। इसके बावजूद सरकार विकास और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका लाभ केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। इसके लिए लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इसके बाद डीए 18 प्रतिशत से बढ़ कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। यह संशोधित दर एक अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी। वहीं नागरिक स्वयंसेवकों के मासिक मानदेय में 2,000 रुपये की वृद्धि का भी प्रावधान किया गया है।

अमेरिका हॉवित्ज़र तोपों के रखरखाव के लिये 1900 करोड़ रु. का पैकेज देगा

नई दिल्ली, 22 जून। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को कहा कि अमेरिका ने भारत की एम777ए2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्ज़र तोपों के रखरखाव और संचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए 23 करोड़ डॉलर (करीब 1,900 करोड़ रुपये) के पैकेज की घोषणा की है। सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह सौदा अब अंतिम रूप दिए जाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करती है और साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि भारत अपनी राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता बनाए रख सके।

एम777ए2 एक अत्याधुनिक और हल्की हॉवित्ज़र तोप है, जिसे भारतीय सेना पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में तैनात करती है।

भाजपा के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ने दराडे के खिलाफ एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, जबकि दराडे सत्तारूढ़ गठबंधन के आधिकारिक उम्मीदवार थे। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे, भाजपा मंत्री गिरीश महाजन और शिवसेना मंत्री उदय सामंत सहित, वरिष्ठ महायुति नेताओं ने इस विवाद को सुलझाने में हस्तक्षेप किया। गहन चर्चा के बाद, गीते ने अपना प्रचार रोकन की घोषणा तो कर दी, लेकिन नामांकन वापसी की समय सीमा बीत जाने के कारण उनका नाम मतपत्र पर बना रहा।

पाकिस्तान ने भारत को युद्ध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार्रवाई नहीं करता, तब तक संधि के सामान्य प्रावधानों को जारी नहीं रखा जा सकता।

एआरवाई न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में आसिफ ने कहा कि यदि पाकिस्तान को लगेगा कि भारत उसके जल प्रवाह में बाधा डाल रहा है, तो वह सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा, "जब भी हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, और पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है, हम भारत के खिलाफ युद्ध करेंगे।" उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत "चिंताजनक गति" से पाकिस्तान के जल अधिकारों को सीमित करने की कोशिश करता है तो इस पर सैन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा।

यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब पाकिस्तान खुद गंभीर आंतरिक संकटों से जूझ रहा है, जिनमें राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ता जल संकट शामिल है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह संकट बाहरी कारणों से अधिक वर्षों से चली आ रही खराब प्रबंधन व्यवस्था का परिणाम है।

नई दिल्ली पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हुए आसिफ ने भारत पर पानी को हथियार बनाने का आरोप लगाया और कहा कि वह चिनाब नदी के प्रवाह में बदलाव कर रहा है तथा जलविज्ञान संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी रोक रहा है। हालांकि, उनके दावे उस समय कमजोर दिखे, जब उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें हाल की घटनाओं की ताजा जानकारी नहीं है और उनकी बात केवल पिछले वर्षों के निरीक्षणों पर निर्भर है।

इस बीच पाकिस्तान का घरेलू जल संकट और गहराता जा रहा है। सिंध और बलूचिस्तान के बड़े हिस्सों में पानी की गंभीर कमी है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं और कृषि उत्पादन पर खतरा मंडरा रहा है। सिंध के सिंचाई विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर पश्चिमी नहर में पानी की 64 प्रतिशत से अधिक कमी है, जबकि राइस नहर और दादू नहर में क्रमशः 38 प्रतिशत और 82 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सुक्कुर बैराज में जल स्तर गिरने से स्थिति और गंभीर हो गई है। क्षेत्रीय नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल वितरण विवादों और बुनियादी ढांचे की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो इसके गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं।

जैसे-जैसे इस्लामाबाद भारत के खिलाफ बयानबाज़ी तेज कर रहा है, आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती उसका पूर्वी सीमा विवाद नहीं, बल्कि वर्षों की उपेक्षा, अक्षमता और कुप्रबंधन है, जिसने उसे दक्षिण एशिया के सबसे अधिक जल-संकटग्रस्त देशों में से एक बना दिया है।

लखनऊ के कोचिंग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चलता है और 12वीं तक के बच्चों का कोचिंग सेंटर भी है। पुलिस के मुताबिक, दोपहर करीब ढ ाई बजे वेयरहाउस में आग लग गई और चंद मिनटों में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई।

दूसरी व तीसरी मंजिल पर मौजूद बच्चे भीतर ही फंस गए। आग इतनी भीषण थी कि आसपास मौजूद लोगों के लिए भीतर जाना संभव नहीं था। दमकल को पहुंचने में भी काफी समय लग गया। इस बीच एक के बाद एक, चार-पांच बच्चों ने छलांग लगा दी।

सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम के साथ एसडीआरएफ ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करीब दो घंटे चले रेस्क्यू के दौरान 15 शव बाहर निकाले गए। कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनमें से कई की हालत गंभीर है।

प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, डीजी फायर सुजीत पांडेय, पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र सेंगर समेत, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर शाम तक राहत-बचाव कार्य जारी था।

आसपास के लोगों में घटना को लेकर काफी आक्रोश था। उनका कहना था कि हादसे के करीब 40 मिनट बाद दमकल की टीम पहुंची। तब तक आग पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले चुकी थी। जब आग पर काबू पाया गया, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। राजधानी में दमकल के इतनी देर से पहुंचने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बिल्डिंग से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तक नहीं था। तीनों तरफ अन्य इमारतें बनी हैं। स्पष्ट है कि बिल्डिंग अवैध है। यही वजह है कि आग लगने पर वहां फंसे लोगों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। वहां फंसे पांच-छह लोग किसी तरह खिड़की का कांच तोड़कर बाहर निकले।

संगठनात्मक फेरबदल को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जाएगा या वे पद पर बने रहेंगे। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, प्रियंका गांधी उन्हें हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रही हैं और उनकी जगह किसी भी अन्य व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

लेकिन, राहुल गांधी शायद अभी उनकी इस मांग को मानने के लिए पूरी तरह तैयार न हों।

दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) का अध्यक्ष बनाकर राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारी की जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी के भीतर यह धारणा है कि उनके बिना राजस्थान में चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है।

लेकिन पार्टी नेतृत्व के सामने अशोक गहलोत को संतुलित करने की चुनौती भी है।

जब तक गहलोत राजस्थान में स्वतंत्र रूप से सक्रिय रहेंगे, वे पूरी ताकत से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि पायलट शीर्ष पद हासिल न कर सकें और मुख्यमंत्री न बन पाएं।

भले ही इसके लिए उन्हें राज्य में भाजपा को फिर से सत्ता में आने में मदद क्यों न करनी पड़े।

यह आसान काम नहीं है, लेकिन पार्टी को इसका समाधान निकालना ही होगा।

कई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, एआईसीसी महासचिवों, सचिवों और अन्य पदाधिकारियों को बदले जाने की संभावना है।

सबसे अधिक जल्दबाजी करने की ज़रुरत पंजाब में है, जहां अगले वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, जहां नेतृत्व इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं है कि इस समय बड़े बदलाव किए जाएं या नहीं।

यह एक ऐसी पार्टी है, जहां फैसले लेना हमेशा कठिन माना जाता है। निर्णय प्रक्रिया में कई बातें मायने रखती हैं। काबिलियत और ठोस राजनीतिक सोच के बजाय, जाति और अन्य समीकरणों या व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के आधार पर फैसले लिए जाते हैं।

राहुल गांधी की "जन जगत" टीम एक बार फिर प्रभावी साबित हो सकती है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि उनके पास न तो कठिन राजनीतिक फैसले लेने की क्षमता है और न ही व्यापक राजनीतिक सोच।

बात बस यह है कि राहुल गांधी को ये लोग और इनका "झोला" वाला अंदाज पसंद है।

प्रियंका गांधी भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनकी वास्तविक भूमिका और प्रभाव का पता बदलावों की घोषणा के बाद ही चल सकेगा।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908